मिलावट का विषैला घोल

हिंदी
विवेक
WE WORK FOR A BETTER WORLD
Issue : 28 June - 04 July 2026

टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड.
मल्टी-स्टेट शेडयूल्ड बैंक
Bharose ka Bank Bhavishya ka Bank

सपनों की कार से कार की चाबी तक

अपने सपनों की कार घर लाएँ
टीजेएसबी ऑटो फाइनेंस लोन के साथ।

ब्याज दर
7.80%*
प्रतिवर्ष से शुरू

*अटी व नियम लागू

www.tjsb.bank.in | ✆ : 022-48897203

अनुक्रमणिका

◆ थाली में परोसा जा रहा विष	सोनम लववंशी	04
◆ मिलावट पर तुकाराम मुंडे की टेढ़ी दृष्टि	लवकुश तिवारी	06
◆ मिलावट के घोल में सतर्कता आवश्यक	डॉ. रामेश्वर मिश्र	08
◆ मिलावट का मेलजोल है	मुकेश जोशी	11
◆ लापरवाही से लाक्षागृह बनते कोचिंग सेंटर	डॉ. अतुल मोहन सिंह	12
◆ जी-7 से मोदी ने कहा भरोसा पैदा करें	रंजीत कुमार	14
◆ शिवसेना का टाइगर अब भी जिंदा है	डॉ. धीरज फूलमति सिंह	17
◆ सुशासन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक	डॉ. लोकेंद्र सिंह	19
◆ भारत के मुसलमान इंडोनेशिया से प्रेरणा लें	ललित गर्ग	21
◆ नई तकनीक, नई चुनौतियां	डॉ. दीपक कोहली	24
◆ मानसून पर अल नीनो का प्रभाव	प्रज्ञा गौतम	26
◆ इधर भी देखें...	संकलन	28
◆ अजब-गजब	-	29

पंजीयन शुल्क

UPI पेमेंट गेटवे के लिए QR कोड स्कैन करें और मैसेज बॉक्स में अपना नाम, पता व सम्पर्क नम्बर दर्ज करें।

वार्षिक मूल्य : 500 रुपये, त्रैवार्षिक मूल्य : 1200 रुपये
पंचवार्षिक मूल्य : 1800 रुपये, आजीवन मूल्य : 25,000 रुपये

कार्यालय : प्लॉट नम्बर 7, आरएससी रोड नम्बर-10, सेक्टर-2,
श्रीकृष्ण बिल्डिंग के पीछे, हनुमान मंदिर बस स्टॉप के समीप, चारकोप,
कांदिवली (पश्चिम), मुंबई- 400067. सम्पर्क : 9594991884

थाली में परोसा जा रहा विष

सोनम लववंशी

कहा जाता है कि जैसा अन्न खाया जाए, वैसा ही मन बनता है, लेकिन जब थाली में शुद्ध भोजन के स्थान पर विष परोसा जाने लगे, तो न शरीर स्वस्थ रह सकता है और न ही मन प्रसन्न एवं संतुलित।

मनुष्य का स्वस्थ जीवन शुद्ध हवा, स्वच्छ पानी और पौष्टिक भोजन पर टिका होता है, लेकिन विडम्बना यह है कि आज सबसे बड़ी चिंता भोजन की शुद्धता को लेकर खड़ी हो गई है। जिस दूध को पोषण का प्रतीक माना जाता है, जिस घी को भारतीय रसोई का गौरव समझा जाता है, जिस मावे और मिठाई से त्योहारों की मिठास जुड़ी होती है, वही आज संदेह के घेरे में हैं। बाजार में चमकते रंग, आकर्षक पैकेज और कम कीमतें अधिकतर उस सच्चाई को छिपा देती हैं कि कहीं न कहीं हमारी थाली में मिलावट का विष परोसा जा रहा है। मिलावट केवल कानून का उल्लंघन नहीं है बल्कि यह समाज के साथ किया गया विश्वासघात है। यह ऐसा अपराध है जिसमें अपराधी का लाभ सीधे उपभोक्ता के स्वास्थ्य की कीमत पर खड़ा होता है। यही कारण है कि खाद्य मिलावट को केवल आर्थिक अपराध नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के रूप में देखने की आवश्यकता है।

सरकारी आंकड़े इस संकट की गम्भीरता को स्पष्ट करते हैं। खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत वर्ष 2022-23 से 2024-25 के बीच 5,18,559 खाद्य नमूनों का विश्लेषण किया गया। इनमें 88,192 मामलों में जुर्माना लगाया गया और 3,614 मामलों में दोष सिद्ध हुए। इसके अतिरिक्त 2024-25 के लिए उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार लगभग 1.70 लाख खाद्य नमूनों में से 17.6 प्रतिशत परीक्षण में असफल पाए गए, जिनमें दूध और उससे जुड़े उत्पादों की हिस्सेदारी उल्लेखनीय रही।

प्रश्न उठता है कि आखिर मिलावट का कारोबार इतना फल-फूल क्यों रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण लालच और जोखिम के बीच असंतुलन है। मिलावट करके उत्पादन लागत घटाई जाती है और मुनाफा कई गुना बढ़ा लिया जाता है। दूसरी ओर निरीक्षण तंत्र की सीमाएं लम्बी कानूनी प्रक्रियाएं, उपभोक्ताओं की जागरूकता की कमी और कई बार स्थानीय स्तर पर कमजोर निगरानी ऐसे कारोबारियों का मनोबल बढ़ाती हैं। जब अपराध से होने वाला लाभ दंड के डर से बड़ा दिखने लगे, तब अवैध गतिविधियां तेजी से फैलती हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो उपभोक्ता भी कई बार अनजाने में इस समस्या को बढ़ावा देते हैं। अत्यधिक सस्ता सामान खरीदने की प्रवृत्ति, दिखावे पर आधारित खरीदारी और बिना प्रमाणित स्रोतों से खाद्य पदार्थ लेना

मिलावट करने वालों को अवसर देता है। त्योहारों के मौसम में जब मांग अचानक बढ़ जाती है, तब नकली मावा, सिंथेटिक पनीर, कृत्रिम रंगों वाली मिठाइयां और निम्न गुणवत्ता वाले तेल बड़ी मात्रा में बाजार में पहुंच जाते हैं। ग्राहक कम कीमत और आकर्षक स्वरूप देखकर संतुष्ट हो जाता है, जबकि वास्तविक कीमत उसके स्वास्थ्य को चुकानी पड़ती है।

आज कदाचित् ही कोई ऐसा खाद्य क्षेत्र बचा हो जहां मिलावट की शिकायतें न आती हों। दूध में पानी, सिंथेटिक रसायन या स्टार्च, घी में सस्ते तेल, पनीर में निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री, मिर्च और हल्दी में कृत्रिम रंग, शहद में अतिरिक्त शर्करा, मसालों में अशुद्ध पदार्थ, फल-सब्जियों पर रासायनिक छिड़काव आदि। यह स्थिति केवल महानगरों तक सीमित नहीं रही बल्कि ये छोटे शहरों और कस्बों तक भी पहुंच चुकी है।

स्वास्थ्य पर इसके दुष्परिणाम बेहद गम्भीर हो सकते हैं। मिलावटी भोजन पाचन तंत्र को प्रभावित करने से लेकर यकृत, गुर्दे और हृदय सम्बंधी समस्याओं तक का कारण बन सकता है। लम्बे समय तक निम्न गुणवत्ता या रासायनिक मिलावट वाले पदार्थों का सेवन बच्चों की वृद्धि, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और बुजुर्गों की प्रतिरोधक क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। कुछ कृत्रिम रंग और अवैध रसायन एलर्जी, विषाक्तता तथा दीर्घकालिक बीमारियों का जोखिम बढ़ा सकते हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इनका प्रभाव कई बार तुरंत दिखाई नहीं देता बल्कि वर्षों बाद गम्भीर रोगों के रूप में सामने आता है।

खाद्य मिलावट की हानि केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, यह पूरे समाज और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। समाधान केवल छापेमारी या दंड में नहीं छिपा है। सबसे पहले निरीक्षण और परीक्षण प्रणाली को और अधिक तकनीकी रूप से सक्षम तथा नियमित बनाना होगा। आधुनिक प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाने, त्वरित जांच व्यवस्था विकसित करने और दोषियों के विरुद्ध समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। बार-बार अपराध करने वालों पर कठोर आर्थिक दंड के साथ प्रभावी अभियोजन भी आवश्यकता है ताकि कानून का भय वास्तविक रूप से अनुभव हो। उपभोक्ताओं की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। खरीदारी करते समय विश्वसनीय स्रोत चुनना, पैकेजिंग और लेबल की जानकारी पढ़ना, बिल लेना, अत्यधिक सस्ते उत्पादों से सावधान रहना और संदिग्ध वस्तुओं की शिकायत सम्बंधित अधिकारियों तक पहुंचाना नागरिक कर्तव्य का हिस्सा होना चाहिए। घरों और विद्यालयों में खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी दीर्घकालिक समाधान का महत्वपूर्ण आधार बन सकता है। तकनीक इस लड़ाई में महत्वपूर्ण सहयोगी सिद्ध हो सकती है। डिजिटल ट्रेसबिलिटी, आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी, क्यूआर आधारित उत्पाद सत्यापन, डेटा विश्लेषण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निरीक्षण प्रणालियां मिलावट की पहचान और रोकथाम को अधिक प्रभावी बना सकती हैं। साथ ही स्थानीय समुदायों, उपभोक्ता संगठनों और मीडिया की सक्रिय भागीदारी भी पारदर्शिता बढ़ाने में सहायक होगी। प्रश्न केवल यह नहीं है कि बाजार में मिलावट क्यों हो रही है बल्कि यह भी है कि क्या हम एक ऐसे समाज को स्वीकार कर सकते हैं जहां लाभ कमाने के लिए लोगों के स्वास्थ्य से समझौता किया जाए? भोजन जीवन का आधार है, इसलिए उसकी शुद्धता पर कोई समझौता स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। यदि सरकार, नियामक संस्थाएं, उद्योग जगत और आम नागरिक मिलकर जिम्मेदारी निभाएं तो मिलावट के इस जाल को बहुत सीमा तक तोड़ा जा सकता है। शुद्ध भोजन किसी विलासिता का विषय नहीं, यह प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। जब तक समाज मिलावट को छोटी चालाकी नहीं एक गम्भीर सामाजिक अपराध मानकर उसके विरुद्ध खड़ा नहीं होगा, तब तक हमारी थाली में स्वाद के साथ जोखिम भी परोसा जाता रहेगा। स्वस्थ भारत का सपना तभी साकार होगा, जब हर नागरिक की थाली में विश्वास, पोषण और शुद्धता समान रूप से परोसी जाएगी। ●●●

मिलावट पर तुकाराम मुंडे की टेढ़ी दृष्टि

लवकुश तिवारी

कार्रवाई

महाराष्ट्र में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर एफडीए की दृष्टि टेढ़ी हो गई है। महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंडे के नेतृत्व में मिलावट के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। मिलावटी समानों की बिक्री करने वालों की अब खैर नहीं होगी।

भारत की संस्कृति में भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि अन्नं ब्रह्म का दर्जा दिया गया है। जिस समाज में अन्न को ईश्वर का स्वरूप माना जाता हो, वहां खाद्य पदार्थों में मिलावट केवल कानून का उल्लंघन नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक अपराध भी है। दुर्भाग्यवश बढ़ते शहरीकरण, उपभोक्तावाद और अधिक लाभ कमाने की प्रवृत्ति ने खाद्य मिलावट को एक संगठित अपराध का रूप दे दिया है। देश की आर्थिक राजधानी मुम्बई भी इस समस्या से अछूती नहीं रही। दूध, मावा, पनीर, मसाले, मिठाइयां, तेल, फल और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट ने आम नागरिक के स्वास्थ्य पर गम्भीर संकट उत्पन्न किया है।

ऐसे समय में महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के आयुक्त तुकाराम मुंडे के नेतृत्व में मिलावट के विरुद्ध चलाया जा रहा व्यापक अभियान जनस्वास्थ्य की रक्षा की दिशा में एक उल्लेखनीय पहल बनकर सामने आया है। यह अभियान केवल कानून लागू करने तक सीमित नहीं है बल्कि समाज में यह संदेश भी देता है कि नागरिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के लिए अब कोई स्थान नहीं होगा।

हाल के महीनों में मुम्बई, कोंकण, पुणे, नासिक, छत्रपति सम्भाजीनगर तथा राज्य के अन्य क्षेत्रों में एफडीए की विशेष टीमों ने एक साथ अनेक स्थानों पर छापेमारी की। इन अभियानों में करोड़ों रुपए मूल्य का मिलावटी मावा, सिंथेटिक दूध, एक्सपायरी पनीर, नकली मसाले तथा रसायनों से कृत्रिम रूप से पकाए गए आम सहित बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री जब्त

की गई। कई अवैध निर्माण इकाइयों को सील किया गया तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई प्रारम्भ की गई।

विशेष चिंता का विषय दूध और दुग्ध उत्पादों में बढ़ती मिलावट है। दूध में यूरिया, डिटर्जेंट, स्टार्च तथा अन्य रसायनों का उपयोग मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक है। इसी प्रकार कृत्रिम रसायनों से तैयार मावा और एक्सपायरी पनीर का उपयोग मिठाइयों एवं खाद्य पदार्थों में किया जाना उपभोक्ताओं के जीवन के साथ सीधा खिलवाड़ है। त्योहारों के दौरान ऐसी गतिविधियों में वृद्धि देखी जाती है, इसलिए एफडीए ने इस अवधि में विशेष निगरानी अभियान भी चलाए हैं।

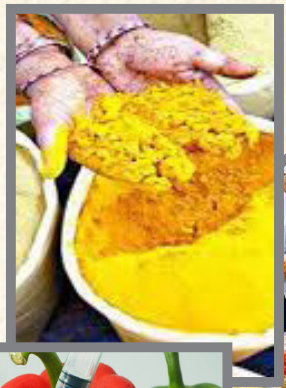

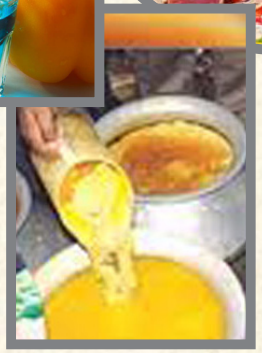

फलों को जल्दी पकाने के लिए प्रतिबंधित रसायनों का उपयोग भी गम्भीर समस्या बन चुका है। कैल्शियम कार्बाइड जैसे रसायनों से पकाए गए आम और अन्य फल देखने में आकर्षक अवश्य लगते हैं, किंतु इनके सेवन से स्वास्थ्य पर दीर्घकालीन दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। एफडीए द्वारा ऐसे फलों की जब्ती यह दर्शाती है कि प्रशासन अब केवल शिकायत मिलने की प्रतीक्षा नहीं कर रहा बल्कि सक्रिय रूप से निगरानी और कार्रवाई कर रहा है।

तुकाराम मुंडे की कार्यशैली प्रशासनिक दृढ़ता और पारदर्शिता के लिए जानी जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा के विषय में किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी सोच के अनुरूप एफडीए ने आधुनिक प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाने, नियमित नमूना परीक्षण, आकस्मिक निरीक्षण तथा विभिन्न विभागों के समन्वय से कार्रवाई को अधिक प्रभावी बनाया है।

हालांकि केवल सरकारी कार्रवाई से इस समस्या का स्थाई समाधान सम्भव नहीं है। समाज की सहभागिता भी उतनी ही आवश्यक है। प्रत्येक नागरिक को खाद्य पदार्थ खरीदते समय उनकी गुणवत्ता, निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि तथा एफएसएसएआई लाइसेंस जैसी जानकारी अवश्य देखनी चाहिए। संदिग्ध खाद्य सामग्री की सूचना सम्बंधित विभाग को देना भी प्रत्येक जागरूक नागरिक का दायित्व है। उपभोक्ता जितना सजग होगा, मिलावटखोरों का नेटवर्क उतना ही कमजोर होगा।

व्यापारिक प्रतिष्ठानों की भी सामाजिक जिम्मेदारी है। अल्पकालिक लाभ के लिए मिलावट का सहारा लेना अंततः समाज, व्यापार और राष्ट्र- तीनों के हितों के विरुद्ध है। भारतीय व्यापार परम्परा सदैव निष्ठा, विश्वास और गुणवत्ता पर आधारित रही है। उसी परम्परा को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।

विद्यालयों, महाविद्यालयों, सामाजिक संगठनों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं को भी खाद्य सुरक्षा के विषय में जनजागरण अभियान चलाने चाहिए। यदि बच्चों और युवाओं में शुद्ध भोजन के प्रति जागरूकता विकसित होगी तो भविष्य में मिलावट के विरुद्ध सामाजिक प्रतिरोध और अधिक मजबूत होगा।

आज आवश्यकता केवल दोषियों को दंडित करने की नहीं बल्कि ऐसी व्यवस्था विकसित करने की है जिसमें मिलावट करना ही कठिन हो जाए। आधुनिक तकनीक, सुदृढ़ कानून, त्वरित न्यायिक प्रक्रिया और सामाजिक जागरूकता- इन चारों के समन्वय से ही खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

महाराष्ट्र में खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा अभियान इसी व्यापक सोच का प्रतीक है। तुकाराम मुंडे के नेतृत्व में हुई सख्त कार्रवाई ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि जनस्वास्थ्य सर्वोपरि है और मिलावटखोरों के लिए कानून का शिकंजा लगातार कसता रहेगा।

अंततः शुद्ध भोजन केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं बल्कि राष्ट्र की मानवीय पूंजी, सामाजिक विश्वास और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा का प्रश्न है।

यदि सरकार, प्रशासन, व्यापारी और समाज मिलकर इस दिशा में सतत प्रयास करें तो मिलावट जैसी सामाजिक बुराई पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। स्वस्थ नागरिक ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते हैं और शुद्ध भोजन उसी सशक्त भारत की आधारशिला है।

●●●

मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री के विरुद्ध सरकार जहां अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है, वहीं मिलावट के प्रति जनजागरण भी उतना ही आवश्यक है। दोनों के संयुक्त प्रयासों से ही इस समस्या पर नियंत्रण सम्भव है।

मिलावट के घोल में सतर्कता आवश्यक

देश के अनेक हिस्सों में नकली व मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री में विशेष रूप से त्योहारों, विवाह के मौसम, धार्मिक आयोजनों तथा मांग बढ़ने वाले अवसरों पर तेजी देखी जाती है। दूध, घी, मावा, पनीर, मिठाइयां, मसाले, खाद्य तेल, शहद, चाय, कॉफी और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले समय-समय पर सामने आते रहते हैं। खाद्य सुरक्षा विभागों द्वारा विभिन्न राज्यों में की जा रही छापेमारी में बड़ी मात्रा में नकली खाद्य सामग्री जब्त की जा रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कुछ असामाजिक तत्व उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की अनदेखी कर केवल अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से मिलावट का कारोबार कर रहे हैं। यही कारण है कि हाल के दिनों में मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध व्यापक कार्रवाई की जा रही है। यह विषय जनस्वास्थ्य, प्रशासन तथा उपभोक्ताओं के लिए गम्भीर चिंता का कारण बन गया है।

भारत जैसे विशाल देश में खाद्य पदार्थों की मांग निरंतर बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, बदलती जीवनशैली तथा तैयार खाद्य पदार्थों के बढ़ते उपयोग ने खाद्य उद्योग का तेजी से विस्तार किया है। इस विस्तार के साथ कुछ व्यापारी अनुचित लाभ कमाने के लिए खाद्य पदार्थों में सस्ते, निम्न गुणवत्ता वाले अथवा हानिकारक रासायनिक पदार्थों की मिलावट करने लगे हैं। बाजार में असली और नकली वस्तुओं के बीच अंतर करना सामान्य उपभोक्ता के लिए कठिन होता जा रहा है। आकर्षक पैकेजिंग, प्रसिद्ध ब्रांडों की नकल तथा कम कीमत का लालच लोगों को आसानी से भ्रमित कर देता है। विशेष रूप से त्योहारों के समय मिठाइयों और दुग्ध उत्पादों की मांग कई गुना बढ़ जाती है। इस अवसर का लाभ उठाकर कुछ लोग सिंथेटिक दूध, नकली मावा, कृत्रिम घी तथा मिलावटी पनीर तैयार कर बाजार में बेच देते हैं। मसालों में कृत्रिम रंग, हल्दी में लेड क्रोमेट, लाल मिर्च में ईंट का चूरा या रंगीन बुरादा, धनिया पाउडर में लकड़ी का बुरादा तथा काली मिर्च में पपीते के बीज जैसी मिलावट के उदाहरण समय-समय पर सामने आते रहते हैं। इसी प्रकार शहद में चीनी की चाशनी, खाद्य तेलों में सस्ते तेलों की मिलावट तथा चाय और कॉफी में निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री मिलाकर उपभोक्ताओं को धोखा दिया जाता है।

डॉ. रामेश्वर मिश्र

मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री से सबसे बड़ी हानि मानव स्वास्थ्य को होती है। ऐसे खाद्य पदार्थों के सेवन से पेट सम्बंधी रोग, उल्टी, दस्त, एलर्जी, त्वचा रोग, यकृत एवं गुर्दे की क्षति, रक्तचाप सम्बंधी समस्याएं तथा हृदय रोग जैसी गम्भीर बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। कुछ रासायनिक रंग और औद्योगिक रसायन लम्बे समय तक शरीर में पहुंचने पर कैंसर

जैसी घातक बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। बच्चों, गर्भवती महिलाओं, वृद्धों तथा कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्तियों पर इसका प्रभाव अधिक गम्भीर होता है।

एक ओर जहां इस समस्या के समाधान के लिए सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानूनों का कठोरता से पालन आवश्यक है। खाद्य पदार्थों का नियमित निरीक्षण, नमूनों की वैज्ञानिक जांच, दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई तथा कठोर दंड की व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू की जानी चाहिए। वहीं उपभोक्ता जागरूकता इस समस्या का सबसे सशक्त समाधान है। प्रत्येक व्यक्ति को खाद्य पदार्थ खरीदते समय उसकी निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, पैकेजिंग की गुणवत्ता, गुणवत्ता प्रमाणन चिह्न तथा निर्माता का विवरण अवश्य देखना चाहिए। अत्यधिक सस्ते दामों पर मिलने वाले खाद्य पदार्थों के प्रति विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। खुली मिठाइयां, बिना लेबल वाले मसाले तथा संदिग्ध गुणवत्ता वाले दुग्ध उत्पाद खरीदने से बचना चाहिए। यदि किसी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता संदिग्ध लगे तो सम्बंधित विभाग में शिकायत करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए।

विद्यालयों, महाविद्यालयों, सामाजिक संस्थाओं तथा स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा के सम्बंध में व्यापक जनजागरण अभियान चलाए जाने चाहिए। लोगों को घरेलू स्तर पर किए जा सकने वाले सामान्य मिलावट परीक्षणों की जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वे प्रारम्भिक स्तर पर संदिग्ध खाद्य पदार्थों की पहचान कर सकें। मीडिया और सोशल मीडिया भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भारतीय संस्कृति में व्यापार को केवल लाभ कमाने का साधन नहीं बल्कि लोकसेवा का माध्यम माना गया है। यदि व्यापारी निष्ठा, गुणवत्ता और सामाजिक उत्तरदायित्व को अपने व्यवसाय का आधार बनाएं तो मिलावट जैसी समस्याओं में उल्लेखनीय कमी आ सकती है। उद्योग संगठनों को भी अपने सदस्यों के लिए आचार संहिता लागू करनी चाहिए तथा गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। सरकार की सतर्कता, कठोर कानून, आधुनिक तकनीक, प्रभावी निगरानी, निष्ठावान व्यापार, जनसहभागिता और उपभोक्ताओं की जागरूकता, इन सभी के संयुक्त प्रयासों से ही इस समस्या पर प्रभावी नियंत्रण सम्भव है। जब समाज का प्रत्येक वर्ग यह संकल्प लेगा कि स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा, तभी मिलावटी खाद्य पदार्थों के इस अवैध कारोबार पर अंकुश लगेगा और प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित, शुद्ध तथा गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सकेंगे। ●●●

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझने के लिए मौलिक एवं संग्रहणीय पुस्तक

पद्मश्री रमेश पतंगे लिखित
'हिंदी विवेक' द्वारा प्रकाशित

हम संघ में क्यों हैं...

संघ विचारों की मूल प्रेरणा, संघकार्य को समझने की प्रक्रिया और इन सभी से संघ स्वयंसेवकों को अनायास मिलनेवाले राष्ट्रबोध और कर्तव्यबोध का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है।

हिंदी विवेक
" We Work For A Better World"

पंजीयन करें
पुस्तक का मूल्य ₹250/-

Draft or Cheque should be drawn in the name of HINDUSTHAN PRAKASHAN SANSTHA HINDI VIVEK

Bank Details : State Bank of India, Branch - Charkop, A/C No. : 00000043884034193, IFSC Code : SBIN0011694

UPI पेमेंट गेटवे के लिए QR कोड स्कॅन करे और मैसेज बॉक्स मे अपना नाम, पता व सम्पर्क नंबर दर्ज करें।

ग्रंथ पंजीकरण हेतु पत्रिका के स्थानीय प्रतिनिधि अथवा कांदिवली कार्यालय में सम्पर्क करें।

प्रशांत : 9594961855, संदीप : 9082898483, भोला : 9702203252, कार्यालय : 9594991884

50+ YEARS OF MOMENTUM
दि कल्याण जनता सहकारी बँक लि.
मल्टी-स्टेट शेड्युल्ड बँक
बदलत्या हवामानात स्वतःची काळजी घ्या...
आणि कल्याण जनता बँकिंग ॲप द्वारे तुमची सर्व बँकिंग कामे करा
- सुरक्षितपणे, सहज आणि घरबसल्या.
अर्थ सहकारेण कल्याणम्
TOLL FREE: 1800 233 1919
kalyanjanata.bank.in
KJSBank

व्यंग्य

मिलावट का मेलजोल है

मुकेश जोशी

पुराने लोग कहते हैं, अब कोई भी चीज शुद्ध नहीं मिलती, हर चीज में मिलावट है। अब इन पुराने लोगों को कौन समझाए कि मिलावट आज की नहीं, बरसों से चली आ रही है। हां, समय के साथ घट बढ़ अवश्य होती रही है। मिलावट घटने का तो प्रश्न ही नहीं, बढ़ती ही जा रही है।

मिलावट पिछले 60 साल से तो मैं ही देख रहा हूं। दूध में पानी मिलने के किस्से कोई आज के नहीं हैं। तब भी कहा जाता था कि भैंस ज्यादा पानी पी जाती थी और आज और भी ज्यादा पी रही है। दूध 5 रु. लीटर भी पतला ही मिलता था और अब 80 रु. लीटर भी।

शुद्ध घी भी केवल नाम का ही शुद्ध है। बड़े-बड़े ब्रांड भी 600-700 रु. किलो घी बेच रहे हैं वो भी चकाचक पैकिंग में, लेकिन दूध की गुणवत्ता को देखते हुए माना जाए तो उसी भाव के दूध से तैयार घी कम से कम 1500 रु. किलो ही पड़ेगा। इससे कम जरा भी नहीं।

पहले तो दूध घी के सैंपल भरे जाते थे। भले ही उन सैंपल के परिणाम 5 साल बाद आते थे, जब समाचारपत्र में छोटी सा समाचार छपता था- कालूराम दूध डेरी का सैम्पल फेल, 500 रु. का अर्थदंड तथा 15 दिन की सजा। अब लगता है सैंपल भरने के दिन लद गए। हो सकता है कि दूध एकदम तगड़ा और घी बिल्कुल शुद्ध मिलने लगा हो क्योंकि नगर पालिकाओं, नगर निगमों में खाद्य अपमिश्रण अमला ही समाप्त कर दिया गया है। स्पष्ट है टेस्ट लैब भी समाप्त कर दी गई अर्थात मिलावट की खुल्ली छूट सरकार की ओर से ही है, चाहे जितनी मिलावट करके खिलाओ। बेचारे आम आदमी का हाजमा इतना कमजोर है कि उसके मिलावट से बने शरीर में शुद्ध दूध, दही, भोजन चला जाए तो अगले को दस्त ही लग जाएं और वो आड़ा पड़ जाए। इसलिए वो बापड़ा शुद्ध खाने पीने की रिस्क ही नहीं लेता। पनीर के नाम पर टोफू खिला रहे हैं होटल वाले। बढ़िया चटखारेदार ग्रेवी डालकर परोस देते हैं, भूखे प्यासे लोग पेट भरने के लिए कुछ भी खा लेते हैं क्योंकि भारत में जितना दूध उत्पादन नहीं होता उससे कई गुना ज्यादा पनीर की खपत हो रही है। पता नहीं इस घोर मिलावटी युग में किसे क्या खिलाया-पिलाया जा रहा है। हम चटोरे भारतीय जहर खा रहे हैं। हर साल शराब पीकर सैकड़ों लोग मर रहे हैं। देसी दारू में सीधे विष मिलाकर पिलाया जा रहा है। लोग मर जाते हैं जिंदे लोग च.. च.. करते हैं। शराब ठेकेदार पर जांच की कार्रवाई की औपचारिकता होती है। ठेकेदार वही दारू बेचकर गरीबों को मारने पर तुले रहते हैं।

खाना-पीना इतना अशुद्ध है कि मिर्च-मसाले भी सारे मिलावट वाले मिलने लगे हैं। मिर्ची में ईंट का बुरादा, धनिये में लीद, हल्दी में कोई भी पीला बेस्वाद पाउडर, काली मिर्च में पपीते के बीज जैसे कई पदार्थ सरेआम मिलाए जा रहे हैं। मिर्च पर लाल कलर स्प्रे करते तो मैंने खुद देखा है। आभूषण में मिलावट का दंश तो हर छोटा-बड़ा आदमी भुगतता ही है। छोटे सुनार से लगाकर अमिताभ जी के ब्रांड तक आभूषण शुद्ध सोने के कोई बना ही नहीं सकता। आप 24 कैरेट गोल्ड खरीदकर लाएं और दो महीने बाद लौटाने जाएं तो 18-20 कैरेट के ही पैसे मिलेंगे। चांदी में गिलेट या जस्तेनुमा कोई धातु की मिलावट तो आम बात है। जब वनस्पति घी सस्ता होता था तो शुद्ध घी में वही मिलाया जाता था, अब वनस्पति भी बराबरी पर आकर गायब होने लगा।

बकरे की जगह पाड़े का गोश्त परोसा जा रहा है, चिकन के नाम पर जाने क्या-क्या तो मिलावट के घालमेल भरे दौर में सब कुछ मिलावट वाला खा-पीकर भी 150 करोड़ लोग जीवित हैं तो मिलावटखोरों का आभारी होना चाहिए कि इनकी मेहरबानी से ही हम बचे हुए हैं। बाकी इंसानों में जो मिलावट घुसी हुई है, वो एक अलग ही विषय है। ●●●

लापरवाही से लाक्षागृह बनते कोचिंग सेंटर

अग्निकांड

लखनऊ में विगत दिनों एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से कई लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि अनेक लोग घायल हो गए। आग क्यों और कैसे लगी, यह अलग मुद्दा है; लेकिन जब आग लगी, तब सुरक्षा के सभी मानक प्रभावी क्यों नहीं हुए, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके।

रामानुज लखन की नगरी लखनऊ के कोचिंग सेंटर भी लाक्षागृह बन चुके हैं। सामान्य-सी चूक या तकनीकी खराबी होते ही ये मोम की भांति जल उठते हैं। ऐसी ही एक हृदय विदारक घटना विगत 22 जून को कोचिंग मंडी के चार मंजिला भवन में घटी। जब दिन के 2 बजे एक मंजिला भवन के बेसमेंट में लगी एसी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग गई। इससे पहले कि कोचिंग सेंटर, पेट क्लिनिक और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में उपस्थित लोगों को कुछ समझ आता, आग ने पूरे भवन को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल दल ने 3 घंटे से अधिक समय के बाद बहुत कठिनाईयों के बाद आग पर नियंत्रण पाया, परंतु कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे 15 होनहारों को आग ने लील लिया।

आखिर फायर सेफ्टी के नाम पर कब तक मात्र खानापूर्ति का खेल चलता रहेगा। कुछ वर्षों में सैकड़ों नागरिक अग्निकांड में जान गंवा चुके हैं। अस्पताल, कोचिंग सेंटर, कारखाने, शॉपिंग मॉल, होटल से लेकर आवासीय भवनों तक लाक्षागृह बने हुए खड़े हैं। जरा सी लापरवाही हुई कि जान-माल पर बन आएगी। लखनऊ की जिस भवन में आग लगी वह अवैध थी। कोचिंग सेंटर, पेट क्लिनिक और अन्य प्रतिष्ठान चल रहे थे।

डॉ. अतुल मोहन सिंह

यह गम्भीर प्रश्न है कि क्या भवन को अग्निशमन विभाग से एनओसी थी? निर्माण मानकों का पालन हुआ था? आपातकालीन निकास मार्ग थे? यदि थे, तो वे उपयोग में क्यों नहीं आए? और यदि नहीं थे, तो इतने लम्बे समय तक प्रशासन की दृष्टि इस पर क्यों नहीं पड़ी? यह केवल भवन स्वामी की ही लापरवाही नहीं है, कोई संस्थान नियमों की अनदेखी करते हुए वर्षों तक संचालित होता है तो कहीं न कहीं प्रशासनिक तंत्र का मौन या भ्रष्ट गठजोड़ सक्रिय है।

लखनऊ में लगी आग ने केवल भवन ही नहीं जलाई बल्कि जिम्मेदारों की संवेदनहीनता, नियामक संस्थाओं की निष्क्रियता और जवाबदेही को उजागर किया है। कोचिंग सेंटर के कई छात्रों की मौत ने देश को झकझोर दिया है। यह केवल हादसा नहीं बल्कि उस सड़ी-गली व्यवस्था का परिणाम है, जो हर त्रासदी के बाद कुछ दिनों तक सक्रिय दिखती है, फिर गहरी नींद में सो जाती है। अग्निकांड की श्रृंखला बताती है कि मानव जीवन का मूल्य घटता

जा रहा है। हर बार वही वक्तव्य सुनाई देता है, 'दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा', 'जांच के आदेश दे दिए गए हैं, कड़ी कार्रवाई होगी आदि। प्रश्न यह है कि क्या जांच और मुआवजा ही शासन का अंतिम दायित्व है? क्या सरकार केवल दुर्घटना के बाद एसआईटी गठित करने, शोक व्यक्त करने और मुआवजा बांटने के लिए हैं? इस काली आग ने न जाने कितने परिवारों के घरों के चिराग बुझा दिए। कितनी ही आंखों की रोशनी छीन ली और एक कालिख पोत दी कानून और व्यवस्था के कर्णधारों के मुंह पर।

वास्तविकता यह है कि अधिकांश शहरों में सुरक्षा भगवान भरोसे है। ऊंची-ऊंची भवनें खड़ी हो रही हैं। सुरक्षा मानकों की हालत चिंताजनक है। अधिकांश बहुमंजिला भवनों में एक ही प्रवेश एवं निकास मार्ग होता है। अग्निशमन उपकरण या तो नहीं होते हैं या वर्षों से निष्क्रिय रहते हैं। आपदा प्रबंधन की नियमित मॉक ड्रिल नहीं होती। भवनों में क्षमता से अधिक लोगों को प्रवेश दिया जाता है। नियम पुस्तकों में सुरक्षा सम्बंधी प्रावधान भले ही हों, किंतु धरातल पर उनका पालन लगभग नगण्य है। इस विडम्बना का सबसे दुखद पक्ष यह है कि हर बड़ी दुर्घटना के बाद जांच समितियां गठित होती हैं, रिपोर्टें तैयार होती हैं, पर अमल नहीं होता। उपहार सिनेमा अग्निकांड से राजकोट और लखनऊ तक, देश ने अनेक त्रासदियों से सबक लेने की बात कही, पर व्यवस्था ने कुछ नहीं सीखा। प्रशासन की स्मृति अत्यंत अल्पकालिक हो चुकी है। कुछ दिनों तक छापेमारी, निरीक्षण और नोटिस जारी करने का नाटक चलता है और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है।

यह हालत केवल प्रशासनिक अक्षमता की नहीं बल्कि नैतिक पतन की भी है। भ्रष्टाचार ने सुरक्षा-व्यवस्था की आत्मा को खोखला कर दिया है। अधिकारी सुविधा शुल्क लेकर आंखें मूंद लेते हैं। भवन स्वामी लाभ कमाने के लिए सुरक्षा उपायों की उपेक्षा करते हैं, इसलिए निर्दोष नागरिक जान गंवाते हैं।

प्रश्न यह भी है कि क्या हमारे शहरों का विकास मानव-केंद्रित है? हम स्मार्ट सिटी, मेट्रो सिटी और विश्वस्तरीय शहरों के निर्माण की बात करते हैं, पर यदि नागरिक सुरक्षित नहीं हैं, तो ऐसे विकास का क्या अर्थ है? किसी भी सभ्य समाज की पहली पहचान उसके नागरिकों की सुरक्षा होती है। सबसे पहले व्यावसायिक भवनों, कोचिंग संस्थानों, अस्पतालों, मॉल, होटल और सार्वजनिक स्थलों का स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट कराया जाए, जिनके पास अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र नहीं हैं या जो मानकों का पालन नहीं करते, उन्हें तत्काल बंद किया जाना चाहिए।

दमकल को अत्याधुनिक संसाधनों से सुसज्जित करना होगा। शहरीकरण के अनुरूप अग्निशमन सेवाओं का विस्तार आवश्यक है। प्रत्येक 6 माह में अनिवार्य रूप से मॉक ड्रिल आयोजित की जाए। स्कूलों और कोचिंग में आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण मिले। जवाबदेही की स्पष्ट व्यवस्था हो। केवल भवन स्वामी ही नहीं बल्कि संबंधित विभागों के अधिकारियों पर भी कठोर कार्रवाई हो।

लखनऊ का अग्निकांड चेतावनी है, यदि अब भी नहीं जागे, तो ऐसे हादसे होते रहेंगे। यह समय आत्ममंथन का है क्योंकि हर अग्निकांड के बाद यदि केवल राख बचती है और व्यवस्था फिर उसी ढर्रे पर लौट जाती है, तो यह केवल लापरवाही नहीं बल्कि एक प्रकार का संस्थागत अपराध है। देश को अब संवेदना नहीं- व्यवस्था चाहिए, जांच नहीं- जवाबदेही चाहिए और आश्वासन नहीं- ठोस कार्रवाई चाहिए, अन्यथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना सम्भव नहीं हो पाएगा। ●●●

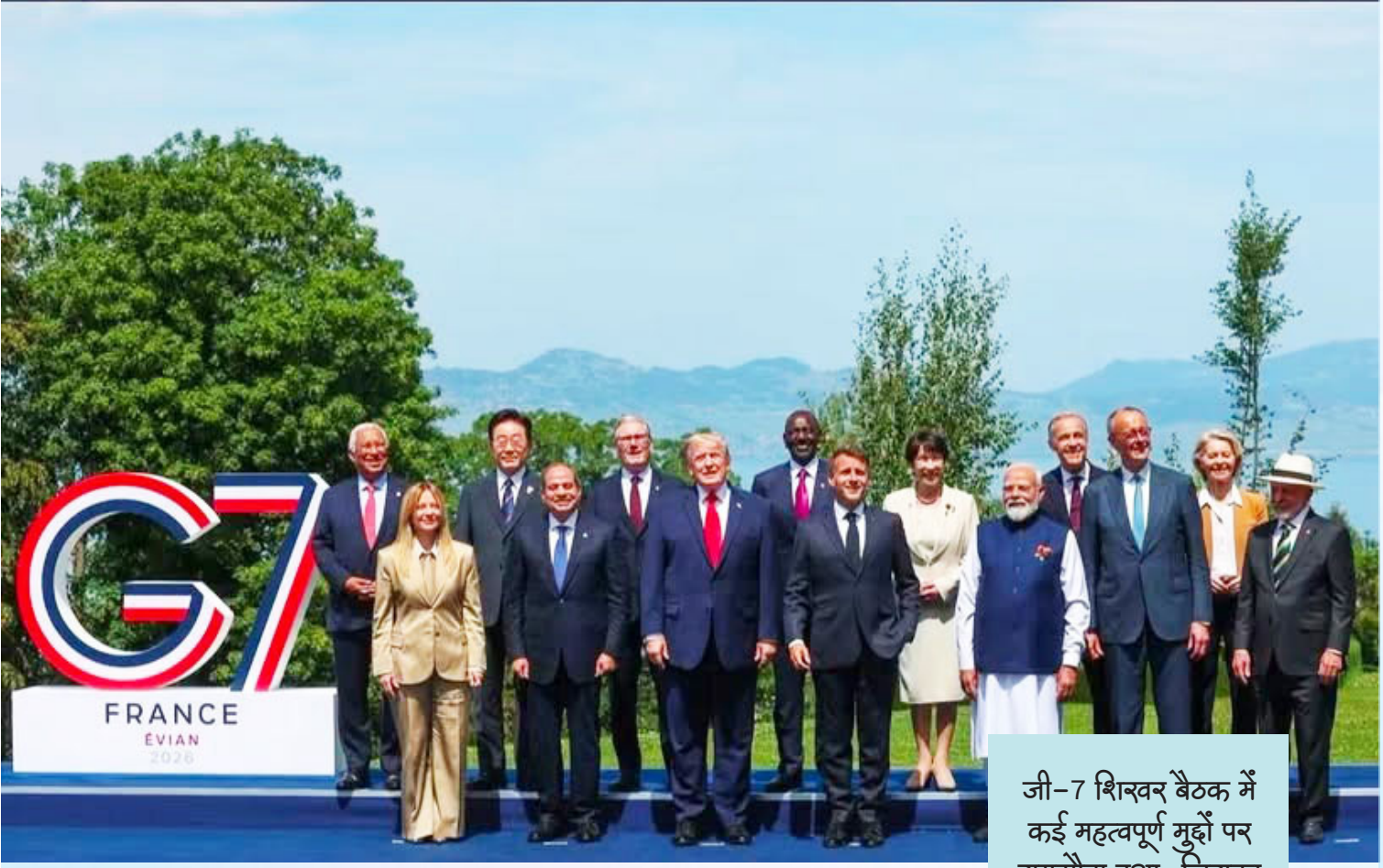

जी-7 से मोदी ने कहा भरोसा पैदा करें

जी-7 शिखर बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर समझौता हुआ, जिसका भारत व वैश्विक बाजार पर प्रभावी व महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। उक्त बैठक में किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई व उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, इस आलेख में विस्तार से चर्चा की गई है।

बैठक

रंजीत कुमार

वैसे तो जी-7 पश्चिमी खेमे के 7 विकसित देशों का संगठन है, लेकिन इसके सदस्य देश अमेरिका, कनाडा, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान द्वारा दुनिया के अहम मुद्दों पर लिए गए निर्णयों को न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित होती है। जी-7 शिखर बैठक के मेजबान देश फ्रांस ने साझेदार देश की दृष्टि से शिखर बैठक में भारत के अलावा केन्या, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और इजिप्ट को भी आमंत्रित कर इसे विकसित और विकासशील देशों की समावेशी बैठक का स्वरूप देने का भी प्रयास किया क्योंकि आज की चुनौतियों का सामना मिलकर ही किया जा सकता है।

हालांकि फ्रांस के एवियान शहर में 16-17 जून तक चले शिखर सम्मेलन के दौरान पश्चिम एशियाई युद्ध, क्रिटिकल मिनरल्स और आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस के बारे में होने वाली चर्चा पर दुनिया की दृष्टि टिकी रही, लेकिन सातों विकसित देशों ने भारत जैसे विकासशील देशों के दूरगामी आर्थिक हितों को प्रभावित करने वाले निर्णय भी लिए। शिखर बैठक के सातों सदस्य देशों ने लगभग 9 साझा प्रस्ताव भी पारित किए।

इसमें भारत की दृष्टि से सबसे अहम था क्रिटिकल मिनरल्स यानी दुर्लभ खनिज के दोहन और उत्पादन के मामले में जी-7 के देशों द्वारा सहयोग की रणनीति पर पहल करना। विदित हो कि चीन ने दुर्लभ खनिज के निर्यात पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे भारत सहित विकसित देशों के आधुनिक उद्योगों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में जी-7 देशों की पहल के साथ भारत का जुड़ना भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा था- वैश्विक राजनीतिक स्थिति पर साझा वक्तव्य, जिसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करने और इस सागरीय क्षेत्र को इसके अनुरूप खुला व मुक्त रखने का आह्वान किया गया। हालांकि इस प्रस्ताव में चीन का सीधा उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर के क्षेत्रों में बलपूर्वक और एकपक्षीय कार्रवाई कर शांति व स्थिरता को भंग करने की किसी भी प्रयास का जोरदार विरोध किया गया और चीन का नाम लिए बिना संकेतों में यह भी कहा गया कि ताईवान के मुद्दों का हल शांतिपूर्वक बातचीत के माध्यम से ही निकाला जाए। भारत भी अंतरराष्ट्रीय मंचों और द्विपक्षीय वार्ताओं में इसी तरह के वक्तव्य जारी करता रहा है। दक्षिण चीन सागर में यदि किसी तरह की अस्थिरता पैदा होती है तो इससे भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ेगा क्योंकि इस समुद्री क्षेत्रों से भारत का आधा से अधिक समुद्री निर्यात और आयात होता है।

साझा वक्तव्य में यूक्रेन युद्ध भी रोकने की अपील करते हुए यूक्रेन को हर तरह की सैन्य और अन्य सहायता जारी रखने का संकल्प लिया गया। यूक्रेन पर आक्रमण जारी रखने तथा रूस के विरुद्ध प्रतिबंधों को भी जारी रखने की घोषणा की गई।

पश्चिम एशिया में ईरान-अमेरिका युद्ध रोकने की हुई सहमति का जी-7 देशों ने स्वागत करते हुए साझा वक्तव्य में कहा कि यह समझौता ईरान को परमाणु हथियारों को प्राप्त करने से रोकने का ऐतिहासिक अवसर प्रदान करता है।

साझा प्रस्ताव में होर्मुज जलडमरूमध्य को अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए खुला रखने और इस क्षेत्र से गुजरने वाले व्यापारिक पोतों पर किसी तरह का टोल या चुंगी लगाने के ईरान की मंशा का विरोध भी किया गया। भारत की दृष्टि से जी-7 का यह प्रस्ताव भारत के अनुकूल कहा जा सकता है क्योंकि भारत को तेल-गैस आपूर्ति के अलावा खाड़ी के देशों को होने वाले भारी निर्यात वाले व्यापारिक पोतों पर ईरान यदि किसी तरह की चुंगी लगाता है तो इससे भारत का आयात-निर्यात महंगा होगा, जिसका प्रतिकूल असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। होर्मुज का समुद्री क्षेत्र बेरोक-टोक भारत के लिए खुला रहना काफी महत्वपूर्ण है। होर्मुज समुद्री क्षेत्रों पर ऊर्जा निर्भरता कम करने और कनाडा के सम्भावित विकल्प के तौर पर उभरने को समर्थन दिया गया। ऊर्जा, खाद्य, ईंधन, स्वास्थ्य और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दे एक-दूसरे से जुड़े हैं। प्रधान मंत्री मोदी ने विकसित देशों के नेताओं को आगाह किया कि वर्तमान अस्थिर दुनिया में व्यापार और तकनीक का प्रयोग हथियार के तौर पर किया जा रहा है। इस कारण दुनिया में परस्पर विश्वास कम होता जा रहा है तथा वैश्विक साझेदारी में पारदर्शिता का अभाव दिखने लगा है।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग के रिश्तों पर जोर देते हुए प्रधान मंत्री ने यह भी कहा कि भारत का दृष्टिकोण हमेशा मानवता-प्रथम का रहा है और अपने अंतरराष्ट्रीय सहयोग के रिश्तों को इसी दृष्टि से समृद्ध करता रहा है। भारत के सतत और समावेशी विकास पर जोर देने की नीति के बारे में उन्होंने कहा कि भारत अपने मूलमंत्र 'सर्वजन हिताए-सर्वजन सुखाए' की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को आगे बढ़ाता रहा है।

प्रधान मंत्री ने विश्व नेताओं को आगाह करते हुए कहा कि हमारी साझेदारी का भविष्य परस्पर विश्वास पर ही निर्भर करता है। हमारी दुनिया में संसाधनों की कमी नहीं बल्कि विश्वास की कमी है। परस्पर विश्वास ही आज की दुनिया में सबसे अहम संसाधन है। हम पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह समझते हैं। हमारा अनुभव यह बताता है कि विकास तभी सबसे अधिक प्रभावी होता है जब हम लोगों की आकांक्षाओं का ध्यान रखते हैं। विश्व की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के नाते जी-7 शिखर बैठक में भारत के विचारों को सुना जाता है और गम्भीरता से लिया जाता है।

इस बार प्रधान मंत्री मोदी ने फ्रांस में जी-7 शिखर बैठक में लगातार 7वीं बार भाग लिया है। पिछली बार उन्हें कनाडा में आयोजित शिखर बैठक में आमंत्रित किया गया था। इस मंच से भारत अपनी बात दुनिया के प्रभावशाली देशों के बीच रखने का अवसर प्राप्त करता है, जहां भारत के प्रधान मंत्री को दुनिया के अग्रणी नेताओं के साथ भी आपसी विषयों पर चर्चा करने और द्विपक्षीय सम्बंधों को आगे बढ़ाने का सुनहरा अवसर भी मिलता है। ●●●

राष्ट्रीय भावनाओं को जाग्रत करनेवाली
सामाजिक व पारिवारिक पत्रिका

हिंदी विवेक
We Work For Better World

पंजीयन करें

सेवा विवेक ग्रंथ

मौलिक एवं संग्रहणीय ग्रंथ, स्वयं एवं परिजनों के लिए पंजीयन करें

ग्रंथ प्रकाशन का उद्देश्य

भारत की आत्मा ...सेवा। जो केवल सहायता या दान नहीं है।

सेवा का सही अर्थ है कर्तव्य, संवेदना और सामाजिक उत्तरदायित्व का समन्वय।

सेवा को भावनात्मक कार्य से आगे ले जाकर विचारशील, सामाजिक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करना।

सेवा के पीछे की भारतीय दृष्टि, प्रेरणा और दर्शन को उजागर करना।

इस विचार को बल देना कि सेवा व्यक्ति को संस्कारित कर समाज को संगठित एवं सशक्त करने का प्रभावी माध्यम है।

आदर्श सेवा कार्यों को संकलित कर समाज के प्रबुद्ध पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करना।

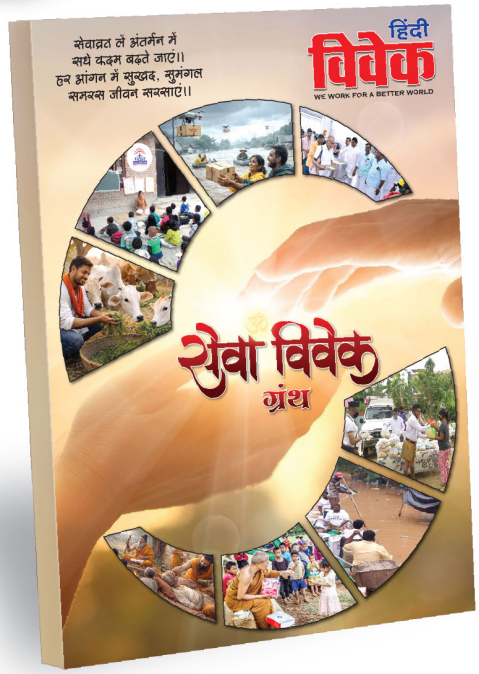

प्रकाशन पूर्व मूल्य
₹ 600/-

ग्रंथ का मूल्य
₹ 700/-

देश के गणमान्य विशेषज्ञों एवं लेखकों की कलम से समृद्ध विषय वस्तु से परिपूर्ण ग्रंथ

UPI पेमेंट गेटवे के लिए QR कोड स्कैन करे और मैसेज बॉक्स मे अपना नाम, पता व सम्पर्क नंबर दर्ज करें।

ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद कृपया 9594991884 पर कॉल करके सूचित करें या व्हाट्सअप करें।

Draft or Cheque should be drawn in the name of : HINDUSTHAN PRAKASHAN SANSTHA HINDI VIVEK

Bank : State Bank of India
Branch : Charkop
A/C No. : 43884034193
IFSC : SBIN0011694

स्थानीय प्रतिनिधि से सम्पर्क करें
कार्यालय : सहारा नांगरे - 9594991884
Email : hindivivekvargani@gmail.com

डॉ. धीरज फूलमति सिंह

महाराष्ट्र की राजनीति गलियारों में जोड़-तोड़ का विद्रोह चल रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) में विरोध की चिंगारी छिटक रही है। कितने सांसद पार्टी का दामन छोड़ कर अन्य पार्टी का हाथ थाम रहे हैं।

शिवसेना का टाइगर अब भी जिंदा है

देश की राजनीति में इस समय विद्रोह का दौर चल रहा है। पहले आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा खेमे में विद्रोह हुआ, फिर तमिलनाडु चुनाव परिणामों के बाद अन्नाद्रमुक (एआईएडीएमके) के सांसदों ने बागी तेवर अपनाए। इसके बाद पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों और विधायकों के दल-बदल ने राजनीतिक हलचल बढ़ाई और अब महाराष्ट्र में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) में एक और फूट सामने आ गई है। इस प्रकार एक के बाद एक चार दलों में उभरे बागी नेताओं ने देश की राजनीति में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है।

महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों के बीच यह हलचल कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 2022 में ही उद्धव के नेतृत्व वाली शिवेसना के कई विधायक और सांसद टूट चुके हैं। इसके परिणामस्वरूप उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी 'शिवसेना' का नाम और चुनाव चिह्न, दोनों गंवाने पड़े थे। अब एक बार फिर पार्टी के कुछ सांसदों के टूटने की आशंका जताई जा रही है। इसे लेकर महाराष्ट्र से दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। शिवसेना-यूबीटी ने सीधे तौर पर इसे भाजपा का षड्यंत्र बताया है।

हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने सार्वजनिक मंच से यह वक्तव्य दिया था कि पहले शिवसेना के लिए शिंदे सेना गुट शब्द का प्रयोग करना पड़ता था, लेकिन जब से उनके 6 सांसद पार्टी से अलग हुए हैं, तब से वह झिझक भी समाप्त हो गई है। अब केवल एक ही गुट बचा है और वह शिवसेना है। शिवसेना (यूबीटी) का अब तो अस्तित्व ही नहीं रहा।

महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में इस पूरे घटनाक्रम को 'ऑपरेशन टाइगर' का भी नाम दिया है। 'ऑपरेशन टाइगर' महाराष्ट्र की राजनीति में प्रयोग किया जा रहा एक शब्द है, जिसे एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की ओर से उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना के नेताओं और सांसदों को अपने पाले में लाने को एक कथित प्रयास के रुप में देखा जाता है। शिवसेना का चुनाव चिन्ह भले धनुष बाण है, लेकिन टाइगर ही उसकी पहचान है, जो बालासाहेब ठाकरे के समय से शिवसेना की पहचान रहा है।

उड़ती चर्चाएं और विभिन्न दावों के अनुसार शिवसेना-यूबीटी के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 -7 सांसद शिंदे गुट के सम्पर्क में हैं और वे संसद के मानसून-सत्र से पहले पाला बदल सकते हैं। इसके अलावा 16 विधायकों के भी शिंदे गुट

के सम्पर्क में होने का दावा किया गया है। विगत रविवार 21 जून को दो सांसदों ने खुलेआम शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होकर इस दावे को और अधिक पुख्ता कर दिया।

शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट में साफ तौर पर विद्रोह के समाचार आने के बाद जिस तरह से राज्यसभा सासंद और प्रवक्ता संजय राऊत ने अनियंत्रित होकर अपशब्दों का प्रयोग करते हुए भाषाई गरिमा को ताक पर रख दिया, यह किसी राजनीतिक व्यक्ति को शोभा नहीं देता। संजय राऊत को समझना चाहिए कि आज शिवसेना का नेतृत्व बालासाहेब ठाकरे नहीं सम्भाल रहे हैं और ना ही यह बालासाहेब ठाकरे का दौर है, जो कोई शिवसैनिक अपशब्द को सहन कर ले।

आज लोग सोचते हैं कि आखिर शिवसेना इतनी कमजोर कैसे हुई। इसका कारण है कि शिवसेना की स्थापना के दौर में इसकी मजबूत कड़ी थी शाखाप्रमुख। एक जमाने में शिवसेना में सांसद, विधायक या नगरसेवक से ज्यादा बड़ी हैसियत और शक्ति शाखा प्रमुख की होती थी। कभी शिवसेना में केवल दो लोगों की चलती थी, एक स्वयं बालासाहेब ठाकरे और दूसरी शिवसेना शाखा प्रमुख! तब एक विधानसभा में 4-5 शाखा प्रमुख हुआ करते थे।

साम, दाम, दंड और भेद का उपयोग कर उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र की सत्ता हथियाने व बाद में भाजपा का साथ छोड़ने के बाद पार्टी और जनता को जोड़े रखने वाली शिवसेना की शाखाप्रमुख वाली यह कड़ी बहुत कमजोर हो गई।

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में आने के बाद बड़े नेताओं के दबाव तथा उनके प्रभाव में आकर पार्टी का कॉरपोरेटाइजेशन होने लगा। अमीर और प्रभावशाली विधायकों के डर एवं ईर्ष्या के कारण जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले शाखाप्रमुखों की शक्ति कम कर दी गई। इसके परिणामस्वरूप शिवसेना पर रसूखदार नेताओं का वर्चस्व बढ़ता गया और गरीब तथा निष्ठावान कार्यकर्ता पार्टी से दूर होते चले गए। आज स्थिति यह है कि शिवसेना के लगभग आधे सांसद भी पार्टी से दूर हो गए हैं।

उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना को अपना अस्तित्व बचाने के लिए गम्भीरतापूर्वक आत्ममंथन करना चाहिए। वह दिन दूर नहीं, जब पार्टी का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाए। इसके लिए संजय राऊत जैसे कुछ अन्य बड़बोले, अनियंत्रित नेताओं को पार्टी से विदाई देनी पड़े तो भी इस बात से झिझक या संकोच नहीं होनी चाहिए। ऐसे में संगठन के भीतर लगातार समस्याएं पैदा करने वाले नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाना ही आसान रास्ता है। ●●●

सुशासन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक

डॉ. लोकेंद्र सिंह

छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक शक्तिशाली हिंदवी स्वराज्य की स्थापना कर विघटनकारी शक्तियों को परास्त किया। हिंदू साम्राज्य दिवस इसी गौरवशाली विरासत का स्मरण कराता है, जिसने भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक चेतना को नई दिशा प्रदान की।

छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के ऐसे अद्वितीय नायक हैं जिन्हें न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य की अनेक पीढ़ियां भी स्मरण करेंगी। इसका मुख्य कारण यह है कि उन्होंने उस युग में, जब आक्रांताओं के अत्याचारों से भारतीय समाज शिथिल हो चुका था, तब हिंदू समाज में एक नई चेतना जगाई। उसके भीतर विश्वास जगाया कि भारत में स्वराज्य की फिर से स्थापना हो सकती है, जहां सब स्वतंत्रता और स्वाभिमान के साथ जी सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि उस कालखंड में विदेशी आक्रमणकारियों ने जबरन धर्मांतरण, सांस्कृतिक विनाश और धार्मिक स्थलों का विध्वंस कर भारतीय सभ्यता को नष्ट करने का प्रयास किया। भारत के स्वाभिमान को झुकाने का प्रयास किया। ऐसी स्थिति में छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक शक्तिशाली हिंदवी स्वराज्य की स्थापना कर इन विघटनकारी शक्तियों को परास्त किया। हिंदू साम्राज्य की स्थापना करके छत्रपति शिवाजी महाराज ने दुनिया को संदेश दिया कि भारत में हिंदुओं का राज्य है।

छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत के स्व को केंद्र में रखकर राज्य की नीतियां बनाईं। अपने संघर्ष के दौरान उन्होंने न केवल सैन्य दृष्टि से अद्वितीय रणनीतियां अपनाईं बल्कि प्रशासन, कृषि, भाषा, मुद्रा और धार्मिक व्यवस्था में भी भारतीय सनातन परम्पराओं के अनुरूप दूरदर्शी सुधार किए। उनका शासन केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं था बल्कि वह भारतीय आत्मगौरव, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और धर्मरक्षा का प्रतीक बन गया।

छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रशासनिक भाषा में से अरबी-फारसी के शब्दों को निकालकर स्वभाषा के गौरव को स्थापित किया। प्रशासनिक व्यवस्था में मुगलों की बनाई व्यवस्थाओं को समाप्त कर स्वराज्य की नई व्यवस्थाएं खड़ी कीं। कृषि में सुधार भी किसानों के हितों को ध्यान में रखकर किए। राज्य के सुचारू संचालन के लिए अष्टप्रधान मंडल का गठन किया, जिसका वर्णन भारतीय आख्यानों में भी आता है। अर्थव्यवस्था में भी आमूलचूल परिवर्तन किए। मुगलों की मुद्राएं बंद करके, स्वराज्य के सिक्के जारी किए। समुद्री सीमाओं को सुरक्षित किया। तोपखाना एवं नौसेना के गठन में स्वदेशी को अधिक महत्व दिया।

हिंदवी स्वराज्य की नींव एवं विस्तार के केंद्र में स्वबोध था, इसलिए हम उनके राज्य से आज भी प्रेरणा लेते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि शिवाजी

के राजनीतिक आदर्श ऐसे थे जिन्हें हम आज भी बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर सकते हैं। उनका उद्देश्य था अपनी प्रजा को शांति देना, सभी जातियों और धर्मों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना, एक कल्याणकारी, सक्रिय और निष्पक्ष प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नौसेना का विकास करना और मातृभूमि की रक्षा के लिए एक प्रशिक्षित सेना तैयार करना।

हिंदू साम्राज्य की स्थापना की घोषणा और छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक, ये भारतीय इतिहास की असाधारण घटनाएं हैं। इन घटनाओं ने भारत की तस्वीर को बदल दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके मंत्रियों ने लम्बे समय से यह महसूस किया था कि राजा के रूप में राज्याभिषेक न होने के व्यावहारिक हानि हैं। यह सच है कि उन्होंने कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी और काफी सम्पत्ति इकट्ठा की थी, उनके पास एक मजबूत सेना और नौसेना थी और वे स्वतंत्र शासक की तरह समाज हित के निर्णय लेते थे, लेकिन उस समय के अन्य राजाओं और मुगल बादशाह के लिए वे केवल एक जमींदार थे, आदिलशाह के लिए वे एक जागीरदार के विद्रोही पुत्र थे।

इस मानसिकता को तोड़ने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक के लिए तैयार हुए। अपने राज्याभिषेक के साथ ही महाराज ने हिंदू पदपादशाही और हिंदू साम्राज्य की स्थापना की घोषणा भी कर दी यानी अब भारत में केवल मुगलों का नहीं अपितु हिंदुओं का भी राज्य है। भारत की प्राचीन और सम्मानित परम्परा के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक सम्पन्न हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज दूरदृष्टा थे, उन्हें मालूम था कि उनके बाद हिंदवी स्वराज्य का विस्तार तभी हो सकता है, जब उसकी वैधता हो। इसलिए भी औपचारिक रूप से सिंहासनारूढ़ होकर हिंदू साम्राज्य को वैधता प्रदान की।

छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे नायक थे, जिन्होंने अपने सपने को अपने साथियों के हृदय में जैसा का तैसा उतार दिया। यही कारण रहा कि उनके जाने के बाद भी हिंदवी स्वराज्य का सपना मरा नहीं अपितु और अधिक पल्लवित-पुष्पित हुआ। एक महान नायक की हृदय भूमि पर अंकुरित हुए बीज ने विशाल वटवृक्ष का रूप धरकर भारत को उसकी पहचान लौटाई। उनके जाने के बाद हिंदवी स्वराज्य के योद्धाओं ने भगवा परचम को सम्पूर्ण भारत पर फहरा दिया था।

●●●

राष्ट्रीय भावनाओं को जाग्रत करनेवाली सामाजिक व पारिवारिक पत्रिका

हिंदी विवेक
We Work For A Better World
मासिक पत्रिका

शुल्क ₹ 500

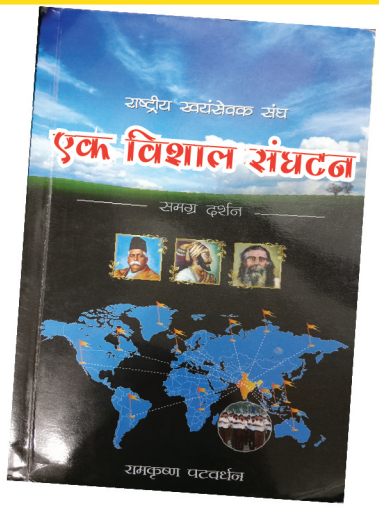

रा. स्व. संघ की स्थापना से लेकर शतकपूर्ति की यात्रा के विभिन्न पड़ावों तथा भविष्य के उद्देश्यों का सम्पूर्ण संकलन व आंकलन करने वाली पुस्तक

UPI पेमेंट गेटवे के लिए QR कोड स्कॅन करे और मैसेज बॉक्स मे अपना नाम, पता व सम्पर्क नंबर दर्ज करें।

ऑनलाईन पंजीयन करने के बाद कृपया 9594991884 पर कॉल करके सूचित करें या व्हाट्सअप करें।

Draft or Cheque should be drawn in the name of : HINDUSTHAN PRAKASHAN SANSTHA-HINDI VIVEK

Bank : Bank of Maharashtra **Branch :** Prabhadevi
A/C No. : 60085108000 **IFSC :** MAHB0000318

सम्पर्क - 9594991884 Email : hindivivekvargani@gmail.com

प्रासंगिक मॉडल

ललित गर्ग

भारतीय मुसलमानों को इंडोनेशिया के मुसलमानों से प्रेरणा लेनी चाहिए। जिससे वे भारत की सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय प्रगति में भी ऐतिहासिक योगदान दे सकते हैं।

भारत के मुसलमान इंडोनेशिया से प्रेरणा लें

विश्व में मुस्लिम समाज की विविधता को समझने के लिए केवल मध्य-पूर्व या पाकिस्तान की ओर देखना पर्याप्त नहीं है। इस्लाम एकरूप नहीं है बल्कि विभिन्न देशों और संस्कृतियों में उसने अलग-अलग स्वरूप ग्रहण किए हैं। इस संदर्भ में इंडोनेशिया एक अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम जनसंख्या वाला देश होने के बाद भी इंडोनेशिया स्वयं को केवल एक इस्लामी राष्ट्र नहीं बल्कि एक बहुलतावादी, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में स्थापित करता है। उसकी राष्ट्रीय विचारधारा पंचासिला और भिन्नेका तुंग्गल इका (विविधता में एकता) यह संदेश देता है कि धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विविधता परस्पर विरोधी नहीं बल्कि पूरक हो सकती हैं।

भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक सम्बंध अत्यंत प्राचीन हैं। दोनों देशों की सभ्यताओं ने हिंदू-बौद्ध परम्पराओं, व्यापारिक सम्पर्कों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से एक-दूसरे को प्रभावित किया है। इंडोनेशिया में इस्लाम का प्रसार मुख्यतः सूफी संतों और व्यापारियों के माध्यम से हुआ। उन्होंने स्थानीय परम्पराओं, लोक कलाओं, संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रतीकों को नकारने की बजाए उन्हें आत्मसात किया। यही कारण है कि आज भी इंडोनेशिया में रामायण और महाभारत के प्रसंग लोकजीवन, नृत्य-नाटिकाओं और सांस्कृतिक आयोजनों का अभिन्न हिस्सा

हैं। वहां के मुसलमान अपनी प्राचीन सांस्कृतिक जड़ों से कटे हुए नहीं बल्कि उनसे संवाद करते हुए दिखाई देते हैं।

इसके विपरीत भारतीय उपमहाद्वीप में पिछले कुछ दशकों में एक ऐसा विमर्श भी विकसित हुआ है, जिसमें धर्म और संस्कृति को एक-दूसरे के विरोधी रूप में प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय मुसलमानों का एक वर्ग अपनी स्थानीय सांस्कृतिक विरासत से दूरी बनाकर स्वयं को केवल मजहबी पहचान तक सीमित करने का प्रयास करता है। यह प्रवृत्ति सामाजिक दूरी और अविश्वास को बढ़ाती है, जबकि भारत की संस्कृति-सभ्यता-विरासत यह प्रमाणित करती है कि भारत का मूल स्वभाव समन्वयवादी और सहिष्णु रहा है।

इंडोनेशिया का सबसे बड़ा संदेश यह है कि धार्मिक पहचान

और राष्ट्रीय पहचान में कोई टकराव नहीं होना चाहिए। वहां मुस्लिम होने के साथ-साथ इंडोनेशियाई होना गर्व का विषय है। राष्ट्रीय एकता, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वो च्च महत्व दिया जाता है। भारत में भी मुसलमानों का विशाल बहुमत देशभक्ति और संवैधानिक मूल्यों में विश्वास रखता है, लेकिन समय-समय पर कुछ कट्टरपंथी प्रवृत्तियां ऐसी छवि निर्मित कर देती हैं, जिससे सम्पूर्ण समुदाय को संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगता है। ऐसे में इंडोनेशिया का अनुभव यह सिखाता है कि धार्मिक समुदायों को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए संवाद, सहभागिता और साझा सांस्कृतिक चेतना अत्यंत आवश्यक है।

महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में भी इंडोनेशिया एक उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। वहां मुस्लिम महिलाएं शिक्षा, व्यवसाय, राजनीति और प्रशासन के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। इंडोनेशिया में महिला राष्ट्रपति तक रही हैं। यद्यपि भारत में भी मुस्लिम महिलाओं ने अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं, फिर भी शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सहभागिता और लैंगिक समानता के क्षेत्र में अभी काफी सुधार की आवश्यकता है। मुस्लिम समाज के भीतर शिक्षा, विशेषकर बालिका शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना समय की मांग है। किसी भी समुदाय का सशक्तीकरण महिलाओं की भागीदारी के बिना सम्भव नहीं है।

धार्मिक सहिष्णुता के क्षेत्र में भी इंडोनेशिया की नीतियां विचारणीय हैं। वहां विभिन्न धर्मों के त्योहारों और सांस्कृतिक आयोजनों को राष्ट्रीय महत्व प्राप्त है। विविधता को राष्ट्र की शक्ति माना जाता है। भारत की सभ्यता भी इसी आदर्श पर आधारित रही है। सर्वधर्म समभाव और वसुधैव कुटुम्बकम् जैसी अवधारणाएं भारतीय संस्कृति की आत्मा हैं। भारतीय मुसलमान यदि अपनी इस साझा सांस्कृतिक विरासत को और अधिक आत्मीयता से स्वीकार करें तो सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को नई ऊर्जा मिल सकती है।

हालांकि यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी एक देश के मॉडल को दूसरे देश पर यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। भारत और इंडोनेशिया की ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां भिन्न हैं। भारत का मुस्लिम समाज अत्यंत विविधतापूर्ण है, जिसमें अनेक भाषाएं, जातीय समूह, क्षेत्रीय संस्कृतियां और धार्मिक परम्पराएं सम्मिलित हैं। इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि भारतीय मुसलमानों को पूरी तरह इंडोनेशियाई मॉडल अपनाना चाहिए बल्कि अधिक उपयुक्त यह होगा कि वे इंडोनेशिया से उन मूल्यों की प्रेरणा लें, जो भारतीय संविधान और भारतीय सभ्यता की मूल भावना के भी अनुरूप हैं- जैसे सहिष्णुता, बहुलतावाद, सांस्कृतिक समन्वय, लोकतांत्रिक आस्था, महिला सशक्तीकरण और राष्ट्रीय एकता।

भारतीय मुसलमानों के लिए यह प्रेरणा का विषय हो सकता है कि वे अपनी धार्मिक निष्ठा को बनाए रखते हुए भारतीय संस्कृति, संविधान और राष्ट्रीय एकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और अधिक सशक्त रूप में अभिव्यक्त करें। भारत और इंडोनेशिया दोनों की साझा सीख यही है कि धर्म का उद्देश्य विभाजन नहीं बल्कि मानवता, करुणा, सह-अस्तित्व और शांति की स्थापना होना चाहिए। यदि भारतीय मुसलमान इंडोनेशिया के समन्वयवादी दृष्टिकोण से प्रेरणा लेते हैं और साथ ही अपनी समृद्ध भारतीय-इस्लामी परम्परा को पुनर्जीवित करते हैं तो वे न केवल अपने समुदाय के विकास में बल्कि भारत की सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय प्रगति में भी ऐतिहासिक योगदान दे सकते हैं।

●●●

आपकी आवाज को बुलंद करने वाली
सम्पूर्ण पारिवारिक व सामाजिक मासिक पत्रिका

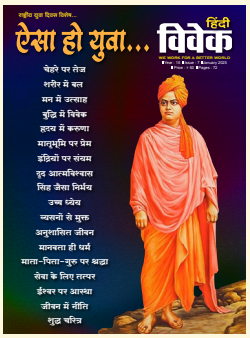

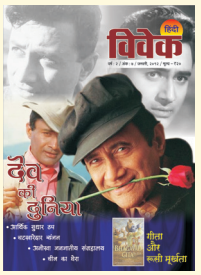

हिंदी विवेक
" We Work For A Better World"

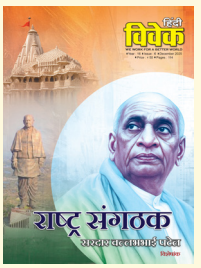

सदस्यता शुल्क

- वार्षिक मूल्य : रु. 500/-
- त्रैवार्षिक मूल्य : रु. 1,200/-
- पंचवार्षिक मूल्य : रु. 1,800/-
- संरक्षक मूल्य : रु. 25,000/-
- विदेशी सदस्यता शुल्क वार्षिक : रु. 5,000/-

खुद ग्राहक बनें व बनाएं

- जन्म दिन तथा अन्य समारोहों में हिंदी विवेक उपहार के रूप में भेंट करें।
- मित्रों, रिश्तेदारों तथा शुभचिंतकों को हिंदी विवेक की सदस्यता प्रदान करें।
- अपने दिवंगत स्नेहीजनों की स्मृति में 11, 21, 51 या 101 पाठकों को सदस्यता दें।
- विवाह के अवसर पर सदस्यता उपहार में दें।
- नववर्ष की शुभकामना के रूप में ग्रीटिंग कार्ड के स्थान पर हिंदी विवेक का सदस्यता रसीद प्रदान करें।

UPI पेमेंट गेटवे के लिए QR कोड स्कैन करें और मैसेज बॉक्स में अपना नाम, पता व सम्पर्क नम्बर दर्ज करें।

हिंदी विवेक कार्यालय

प्लॉट नम्बर 7, आरएससी रोड नम्बर 10, सेक्टर - 2, श्रीकृष्ण बिल्डिंग के पीछे,
हनुमान मंदिर बस स्टॉप के समीप, चारकोप, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई - 400067

सम्पर्क : +91 95949 91884

hindivivekvargani@gmail.com / hindivivekadvt@gmail.com

हाय! ये बढ़ते बिजली बिल

नए स्मार्ट मीटर

डॉ. दीपक कोहली

नए स्मार्ट मीटरों की स्थापना के बाद से उपभोक्ताओं के मासिक बिजली बिलों में अप्रत्याशित और भारी उछाल आया है, जिसने आम जनता के बीच गहरे असंतोष और आक्रोश को जन्म दिया है।

बिजली विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर आज चर्चा का विषय बने हुए हैं। अनेक उपभोक्ताओं का कहना हैं कि पुराने मीटर की तुलना में नए स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनके बिजली बिल में उल्लेखनीय वृद्धि हुई हैं। इस कारण लोगों के मन में यह शंका पैदा होना स्वाभाविक है कि कहीं नए मीटर बिजली की खपत को अधिक तो नहीं दर्शा रहे हैं या फिर इनके मापन का पैमाना पुराने मीटरों से अलग तो नहीं है।

स्मार्ट मीटर आधुनिक डिजिटल तकनीक पर आधारित उपकरण है। ये उपभोक्ता द्वारा उपयोग की गई बिजली को बहुत सटीकता के साथ रिकॉर्ड करते हैं और उसकी जानकारी स्वतः बिजली विभाग तक पहुंचाते हैं। पुराने इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटरों में समय के साथ घिसावट आ जाती थी, जिससे वे कई बार वास्तविक खपत से कम बिजली दर्ज करते थे। कुछ मामलों में तकनीकी खराबी या छेड़छाड़ के कारण भी बिजली की सही गणना नहीं हो पाती थी। इसके विपरीत स्मार्ट मीटर अत्यधिक संवेदनशील और सटीक होते हैं, इसलिए वे बिजली की वास्तविक खपत को दर्ज करते हैं। यही कारण है कि कई उपभोक्ताओं को ऐसा अनुभव होता है कि नए मीटर लगने के बाद बिल अचानक बढ़ गया है।

देश में उपयोग होने वाले सभी बिजली मीटरों को निर्धारित मानकों और परीक्षण प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। यदि कोई मीटर मानक के अनुरूप नहीं पाया जाता तो उसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में स्मार्ट मीटर और पुराने मीटर दोनों बिजली की खपत को यूनिट अर्थात किलोवाट-घंटा के आधार पर ही मापते हैं। अंतर केवल इतना है कि स्मार्ट मीटर अधिक सटीकता से हर छोटी-बड़ी खपत को दर्ज कर लेते हैं, जबकि पुराने मीटरों में कभी-कभी कुछ खपत रिकॉर्ड नहीं हो पाती थी।

स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को लेकर आम जनता में इस समय गहरा रोष और असंतोष देखा जा रहा है। उपभोक्ताओं की सबसे पहली और बड़ी आपत्ति इस बात को लेकर है कि बिजली विभाग द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना या घर के सदस्यों की सहमति के, पुराने मीटर बदलकर नए स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा रहे हैं, जिसे लोग अपनी निजता और पारदर्शिता का उल्लंघन मान रहे हैं। इसके साथ ही जनता का एक बड़ा आरोप यह भी है कि नए मीटर लगने के बाद से उनके मासिक बिजली बिलों में अप्रत्याशित रूप से भारी बढ़ोतरी हुई है, यहां तक कि सामान्य उपयोग के बावजूद बिल पहले की तुलना में दोगुना या तीन गुना तक आ रहा है। लोगों का मानना है कि ये नए डिजिटल मीटर सामान्य से अधिक तेजी से चलते

हैं और इसमें 'जंपिंग' की समस्या है। इसके अलावा रीचार्ज समाप्त होते ही बिना किसी मानवीय चेतावनी के अचानक बिजली कट जाने और तकनीकी कमियों के कारण गलत बिलिंग होने से उपभोक्ताओं में असुरक्षा और अविश्वास की भावना पैदा हो गई है। इस तकनीकी बदलाव को लोग एक आर्थिक बोझ और जबरन थोपी गई व्यवस्था के रूप में देख रहे हैं, जिसके कारण जगह-जगह विरोध प्रदर्शन और शिकायतें देखने को मिल रही हैं। उपभोक्ताओं का आरोप है कि बिजली के उपकरणों और खपत के ढर्रे में बिना किसी बदलाव के भी बिल अचानक डेढ़ से दो गुना तक बढ़ गए हैं, जिसने उनके घरेलू बजट को पूरी तरह से चरमरा दिया है। ऐसे में जब तक बिजली उपभोक्ताओं को विश्वास में लेकर उनकी शिकायतों का त्वरित निवारण नहीं किया जाता और इस पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता नहीं लाई जाती, तब तक आधुनिकरण के इस प्रयास को लेकर जन-असंतोष का कम होना असम्भव है। कई लोगों का कहना है कि जब वे गांव गए थे तब उनका घर बंद था और जब वापस आए तब लाइट बील देखकर चौक गए क्योंकि बंद घर का मासिक बिल लगभग 600-700 रु. तक आया हुआ था।

बताया जाता है कि स्मार्ट मीटरों का एक अन्य लाभ यह है कि इनके माध्यम से बिजली आपूर्ति से जुड़ी तकनीकी समस्याओं का शीघ्र पता लगाया जा सकता है। यदि किसी क्षेत्र में बिजली बाधित होती है या लाइन में कोई खराबी आती है तो सम्बंधित सूचना तुरंत नियंत्रण केंद्र तक पहुंच सकती है। इससे मरम्मत कार्य में तेजी आती है और उपभोक्ताओं को कम समय तक असुविधा का सामना करना पड़ता है। भविष्य में जब देश में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा का उपयोग और अधिक बढ़ेगा, तब स्मार्ट मीटर ऊर्जा प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

फिर भी यह भी स्वीकार करना होगा कि स्मार्ट मीटरों को लेकर लोगों की चिंताएं पूरी तरह निराधार नहीं कही जा सकतीं। यदि किसी क्षेत्र में बड़ी संख्या में उपभोक्ता अचानक अत्यधिक बिल आने की शिकायत कर रहे हैं तो बिजली विभाग का दायित्व है कि वह पारदर्शिता के साथ मीटरों की जांच कराए और उपभोक्ताओं की शंकाओं का समाधान करे। लोगों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे अपने मीटर की परीक्षण रिपोर्ट देख सकें और आवश्यकता पड़ने पर उसकी स्वतंत्र जांच भी करा सकें। विश्वास और पारदर्शिता के बिना किसी भी नई तकनीक को सफलतापूर्वक लागू करना कठिन होता है। ●●●

स्वयं के लिए और अपने परिजनों के लिए ग्रंथ का पंजीयन करें

इस ग्रंथ में आप पढ़ेंगे

- संघ में हो रहे अनगिनत सेवा कार्यों का परिणाम क्या है?
- डॉ. हेडगेवार जी से लेकर डॉ. मोहन भागवत जी तक के सभी सरसंघचालकों का दिशादर्शन...
- राजनीति को केंद्र में न रखकर राष्ट्रीयत्व को क्यों केंद्र में रखा?
- भारत के सम्मुख चुनौतियां और संघ कार्य का प्रभाव
- संघ विचारधारा और परिवर्तन

जैसे विविध मौलिक विषय

ग्रंथ का मूल्य ₹700/-

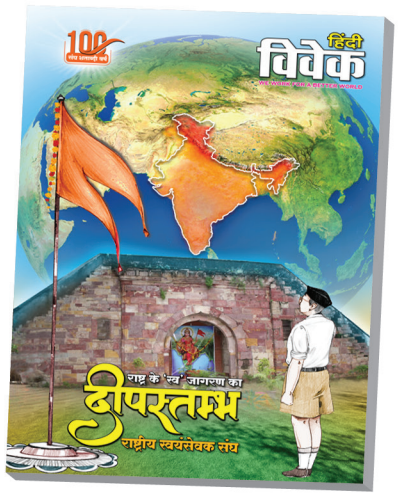

ईमेल – hindivivekvargani@gmail.com

Draft or Cheque should be drawn in the name of HINDUSTHAN PRAKASHAN SANSTHA HINDI VIVEK

Bank Details : State Bank of India, **Branch -** Charkop, A/C No. : 00000043884034193, IFSC Code : SBIN0011694

ग्रंथ पंजीकरण हेतु पत्रिका के स्थानीय प्रतिनिधि अथवा कांदिवली कार्यालय में सम्पर्क करें।

सम्पर्क

प्रशांत : 9594961855, संदीप : 9082898483

भोला : 9702203252, कार्यालय : 9594991884

UPI पेमेंट गेटवे के लिए QR कोड स्कॅन करे और मैसेज बॉक्स मे अपना नाम, पता व सम्पर्क नंबर दर्ज करें।

प्रज्ञा गौतम

मानसून पर अल नीनो का प्रभाव

अल नीनो भारत के मानसून को कमजोर करने वाली महत्वपूर्ण वैश्विक जलवायु घटनाओं में से एक है। इसके कारण वर्षा की कमी, कृषि उत्पादन में गिरावट, भूजल स्तर में कमी तथा जल संकट जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

भारत मौसम विज्ञान के बुलेटिन के अनुसार भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में अल नीनो सक्रिय हो चुका है। जब भी प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति विकसित होती है तो इसका सीधा असर भारतीय मानसून पर पड़ता है। सामान्यतः अल नीनो के कारण भारत में मानसूनी वर्षा कमजोर हो जाती है। विदित हो कि हमारे देश में किसान दक्षिण-पश्चिम मानसून पर अत्यधिक निर्भर हैं। देश की लगभग आधी कृषि भूमि आज भी वर्षा आधारित है। वर्षा की कमी से कृषि उत्पादन, जल उपलब्धता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होते हैं।

कैसे बनता है अल नीनो

अल नीनो कुछ वर्षों के अंतराल में प्रकट होने वाली एक असामान्य जलवायु घटना है। प्रशांत महासागर की सतह का जल सामान्य से अधिक गर्म हो जाना इस स्थिति को जन्म देता है। यदि यह तापमान वृद्धि कुछ माह तक बनी रहती है तो इससे अल नीनो की सम्भावना बन जाती है। इससे वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण में परिवर्तन आता है। मानसून को संचालित करने वाली हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। समुद्री सतह का गर्म पानी जो पश्चिमी प्रशांत की ओर बढ़ता था, भूमध्यरेखीय पूर्वी और मध्य प्रशांत महासागर (दक्षिणी अमेरिका के तट) की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। जिसके परिणामस्वरूप वर्षा की मात्रा घट जाती है या उसका वितरण असमान्य हो जाता है।

हालांकि हर अल नीनो वर्ष में सूखा पड़े, यह आवश्यक नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक आंकड़े बताते हैं कि भारत के कई बड़े सूखे अल नीनो वर्षों से जुड़े रहे हैं। चेन्नई में भारतीय मौसम विभाग ने इसके स्तर बताए हैं। तापमान में 0.1 से 1 डिग्री सेल्सियस के अंतर को कमजोर, 1- 1.5 का अंतर मध्यम, 1.5- 2 का अंतर मजबूत और 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा को सुपर अल नीनो माना जाता है। वर्तमान अल नीनो में यह अंतर 2.5 पहुंच सकता है। हमारा सामना इस बार सुपर अल नीनो से है।

भारतीय मानसून पर प्रभाव

हमारे यहां जुलाई से लेकर सितम्बर के बीच अल नीनो का सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा। बताया जा रहा है कि इसका असर फरवरी 2027 तक रह सकता है। अल नीनो के कारण मानसून के आगमन में देरी हो सकती है। इस दौरान हिंद महासागर की ओर चलने वाली व्यापारिक पवनें कमजोर पड़ जाती हैं। मानसूनी हवाओं में नमी कम होती है, जिससे कुल वर्षा सामान्य से कम हो सकती है। यदि इस वर्ष अल नीनो शक्तिशाली रहा तो वर्षा में 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक कमी हो सकती है। विशेष रूप से

जुलाई-अगस्त माह के दौरान कम वर्षा होगी। वर्षा का वितरण भी असमान होगा। ऐसे में लम्बे शुष्क अंतराल बढ़ जाते हैं। तापमान सामान्य से अधिक रहता है। इन परिस्थितियों का सबसे अधिक प्रभाव कृषि क्षेत्र पर पड़ता है।

कृषि पर प्रभाव

केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ओडिसा, गुजरात, बिहार, झारखंड और तमिलनाडु को 12 सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्यों की सूची में रखा है। राजस्थान जो पहले से ही शुष्क और अर्ध-शुष्क राज्य है। यहां खरीफ की फसलें मुख्यतः वर्षा पर निर्भर रहती हैं। चारे की कमी से पशुपालन पर असर होगा। पश्चिमी राजस्थान में सूखे जैसी स्थिति हो सकती है। मध्य भारत में मक्का और सोयाबीन की फसल प्रभावित होगी। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में धान के उत्पादन पर असर पड़ेगा। उत्तर-पूर्व भारत में व्यापक रूप से धान, मक्का और गन्ना बोया जाता है। दक्षिणी राज्यों में भी चावल प्रमुख खाद्यान्न है। यह निश्चित है कि अल नीनो सक्रिय रहा तो इन खाद्यान्न फसलों को हानि होगी। छोटे किसान अधिक प्रभावित होंगे। भू-जल दोहन से जलाशय सूख जाएंगे। तापमान अधिक रहने से कीट-पतंगे सक्रिय रहेंगे।

जल संसाधनों पर प्रभाव

अल नीनो का सबसे गम्भीर प्रभाव जल संसाधनों पर पड़ता है। यदि मानसून कमजोर रहता है तो बड़े बांध और जलाशय पर्याप्त मात्रा में नहीं भर पाते। इससे सिंचाई और पेयजल दोनों प्रभावित होते हैं। कम वर्षा होने पर किसान अधिक ट्यूबवेल चलाते हैं। इससे भूजल तेजी से नीचे जाता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में यह समस्या पहले से गम्भीर है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुएं, तालाब और हैंडपम्प सूखने लगते हैं। कई क्षेत्रों में पानी टैंकरों से पहुंचाना पड़ सकता है। बड़े शहरों में भी जलापूर्ति पर दबाव बढ़ सकता है। बढ़ती जनसंख्या और सीमित जल संसाधन समस्या को और गम्भीर बनाते हैं।

खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव

कम वर्षा का असर केवल किसानों तक सीमित नहीं रहता। यदि धान, दालें, तिलहन और अन्य फसलों का उत्पादन घटता है तो खाद्यान्न कीमतों में वृद्धि हो सकती है। खाद्यान्न उत्पादन में 10 से 15 प्रतिशत की कमी आ सकती है। दालों और खाद्य तेलों की महंगाई बढ़ सकती है। सरकार को अतिरिक्त आयात करना पड़ सकता है। ऐसे स्थिति में समाज का निचला वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ सकती है। शहरी क्षेत्र में भी मजदूर और कामगार लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं।

●●●

आपकी आवाज को बुलंद करने वाली
सम्पूर्ण पारिवारिक व सामाजिक मासिक पत्रिका

पुस्तकों का खजाना

हिंदी विवेक
" We Work For A Better World"

10 से अधिक प्रतियां बुक करने पर विशेष छूट दी जाएगी

Draft or Cheque should be drawn in the name of HINDUSTHAN PRAKASHAN SANSTHA HINDI VIVEK

• Bank Details : State Bank of India • Branch : Charkop,
• A/C No. : 00000043884034193 • IFSC Code : SBIN0011694

पंजीकरण हेतु पत्रिका के स्थानीय प्रतिनिधि अथवा कांदिवली कार्यालय में सम्पर्क करें।

प्लॉट नम्बर 7, आरएससी रोड नम्बर-10, सेक्टर-2, श्रीकृष्ण बिल्डिंग के पीछे, हनुमान मंदिर बस स्टॉप के समीप, चारकोप, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई- 400067

UPI पेमेंट गेटवे के लिए QR कोड स्कैन करें और मैसेज बॉक्स में अपना नाम, पता व सम्पर्क नम्बर दर्ज करें।

प्रशांत : 9594961855 / भोला : 9930016472 / संदीप : 7045961331
कार्यालय : 9594991884 Email : hindivivekvargani@gmail.com

एलिफेंटा द्वीप पर 1500 साल पुरानी वास्तुकला मिली

अरब सागर में मुम्बई के तट से दूर एलिफेंटा द्वीप पर पत्थर और ईंटों से बना एक जलाशय मिला है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह 1500 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस खोज से यह सिद्ध होता है कि पहले भी उन्नत इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता था।

विशेषज्ञों के अनुसार यह संरचना इस बात का प्रमाण है कि यहां के निवासियों ने पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की थी। ऐसा करते समय उन्होंने मौसमी मानसून के अनुमान और एलिफेंटा द्वीप के चट्टानी भूभाग, दोनों बातों का ध्यान रखा था।

कोंकण तट पर नए सूक्ष्म छिद्रण जीव की खोज

पुणे स्थित अघारकर अनुसंधान संस्थान (एआरआई) के वैज्ञानिक डॉ. तुषार कौशिक के नेतृत्व में एक टीम ने फोरामिनिफेरा की एक नई प्रजाति की खोज की है। फोरामिनिफेरा एककोशिकीय जीवों का समूह है जो 5 करोड़ वर्षों से अधिक समय से विश्व के महासागरों में निवास कर रहा है। इस नई प्रजाति का नाम पोर्टाट्रोचैमिना भरतेंसिस रखा गया है और यह महाराष्ट्र के कोंकण तट पर स्थित एक छोटे से मुहाने, जैतापुर क्रीक के तलछट में पाई गई है।

मेघालय में सूक्ष्म घोंघों की दो नई प्रजातियां मिलीं

शोधकर्ताओं ने मेघालय की गुफाओं में रहने वाले सूक्ष्म घोंघों की दो नई प्रजातियों की पहचान की है। 'जियोरिसा मेघालयेंसिस' और 'एकमेला बेनसोनी' नामक ये घोंघे इतने छोटे हैं कि इन्हें नंगी आंखों से देखना कठिन है। यह खोज पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध जैव विविधता को रेखांकित करती है।

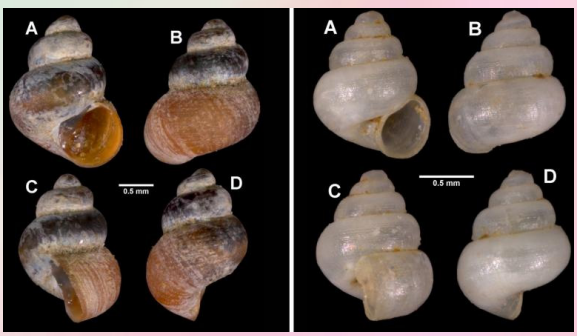

ओडिशा में मिले 1.5 करोड़ वर्ष पुराने समुद्री जीवाश्म

ओडिशा के मयूरभंज जिले के बारीपदा के पास छात्रों और शोधकर्ताओं की एक टीम को करीब 1.5 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म मिले हैं। इनमें शार्क के दांत, शार्क की रीढ़ की हड्डी के हिस्से और अन्य जीवाश्म अवशेष शामिल हैं। इस खोज को इस बात का महत्वपूर्ण प्रमाण माना जा रहा है कि आज का यह क्षेत्र कभी समुद्र के नीचे था।

क्या आपको पता है कि दुनिया में अनेक प्रकार की जातियां और समुदाय हैं? इन जातियों और समुदायों के लोगों की अपनी-अपनी परम्पराएं और रीति-रिवाज होते हैं। इनमें से कुछ परम्पराओं और रीति-रिवाजों के बारे में जानकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। आज हम आपको ऐसी ही कुछ अनोखी परम्पराओं और रीति-रिवाजों से अवगत कराते हैं।

शव के साथ डांस

मेडागास्कर में रहने वाली मालागासी जनजाति में एक फामादिहाना नाम की परम्परा का पालन किया जाता है। इस रिवाज का पालन हर 7 साल पर किया जाता है। इस रिवाज में जनजाति के लोग अपने पूर्वजों के शव को बाहर निकालते हैं और फिर उनको नए कपड़े में लपटते हैं। इसके बाद गाना गाते हैं और कब्र के चारों ओर डांस करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से उनके पूर्वज सुखी और सम्पन्न रहने का आशीर्वाद देते हैं।

नमक मांगना माना जाता है जुर्म

मिस्र में नमक मांगना जुर्म माना जाता है। यहां पर आप किसी के घर मेहमान बनकर जाते हैं, तो भूलकर भी खाने में नमक नहीं मांगे। मिस्र में नमक मांगना मेजबान का अपमान माना जाता है।

फुकेत वेजिटेरियन फेस्टिवल

थाईलैंड के फुकेट में हर साल वेजिटेरियन फेस्टिवल मनाया जाता है। इस दौरान हिंसक गतिविधियां देखी जाती हैं। इस फेस्टिवल से 9 दिन पहले से लोग मांस खाना बंद करते हैं, लेकिन इस फेस्टिवल में बेहद अजीबोगरीब परम्परा का पालन किया जाता है। यहां पर लोग अपने गाल और होठों को नुकीले चाकू या तलवार से चीरते हैं। लोगों का मानना है कि ऐसा करने से ईश्वर उनकी रक्षा करते हैं।

जलती आग पर चलना

चीन में भी लोग एक अजीब रिवाज का पालन करते हैं। यहां पर पति को गर्भवती पत्नी को लेकर जलती आग पर नंगे पैर चलना पड़ता है। माना जाता है कि ऐसा करने से डिलिवरी में आसानी होती है।

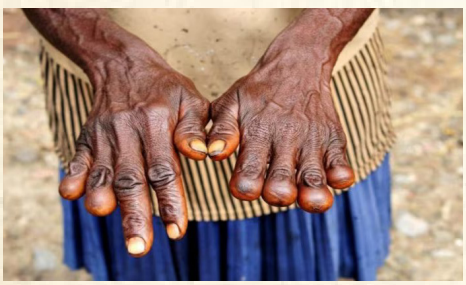

काटनी पड़ जाती है अंगुली

इंडोनेशिया की दानी जनजाति में एक अजीबोगरीब परम्परा का पालन किया जाता है। यहां पर परिवार में किसी की मृत्यु होने पर महिलाओं को अपनी अंगुली काटनी पड़ती है। हालांकि कुछ समय से इस परम्परा पर बैन लगा दिया गया है, लेकिन कुछ बुजुर्ग लोग अभी भी इस परम्परा को मानते हैं।

पितांबरी® टूर्स और ट्रॅवल्स

दुनिया घूमिए, अपनापन पाइए।

भारत के अद्वितीय स्थलों की सैर!

अष्टविनायक दर्शन
२ रातें / ३ दिन

श्री मयूरेश्वर | श्री सिद्धिविनायक | श्री बल्लाळेश्वर | श्री वरदविनायक

श्री चिंतामणी | श्री गिरीजात्मज | श्री विघ्नेश्वर | श्री महागणपती

स्टॅच्यू ऑफ युनिटी और वडोदरा
३ रातें / ४ दिन

महाबलेश्वर और वाई टूर
२ रातें / ३ दिन

श्री समर्थ रामदास द्वारा स्थापित ११ मारुती दर्शन
२ रातें / ३ दिन

टूर में शामिल :

- एसी बस / गाड़ी सफर और स्थानीय पर्यटन स्थलों की सैर
- ठहरने के लिए प्रीमियम होटल्स
- स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था
- जानकार गाइड और सभी प्रवेश टिकट

हमारे अन्य टूर्स

कोस्टल कर्नाटक	केरल	हंपी बदामी	राजस्थान- मेवाड़ / मारवाड़	कश्मीर
(बाय रोड) ६ रातें / ७ दिन	(बाय फ्लाईट) ४ रातें / ५ दिन	(बाय रोड) ५ रातें / ६ दिन	(बाय फ्लाईट) ५ रातें / ६ दिन	६ रातें / ७ दिन

जल्द ही हिमाचल और नैनीताल टूर्स का आयोजन

नेपाल टूर ! (बाय फ्लाईट) - ७ रातें / ८ दिन

Attractive Discount on Select Tours Costing more than ₹12000/-

अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क:

8657968481, 8530015838, 9702963400, 8657307352, 8828913131